

भारतीय खाद्य निगम

बनाम

मैसर्स चंदू कंस्ट्रक्शन और अन्य

10 अप्रैल 2007

[तरुण चटर्जी और डी.के. जैन, जे.जे.]

मध्यस्थता अधिनियम, 1940-एस. 30-मध्यस्थ द्वारा दिए गए पंचाट को रद्द करने की न्यायालय की शक्ति-माना गया: जब मध्यस्थ ने स्वयं या कार्यवाही का कदाचार किया तो न्यायालय पंचाट में हस्तक्षेप कर सकता है-तथ्यों पर, मध्यस्थ ने अनुबंध में स्पष्ट शर्तों की अनदेखी करते हुए पक्षों के बीच समझौते की अवहेलना की- इस प्रक्रिया में, मध्यस्थ ने खुद को गलत निर्देशित किया और गलत आचरण किया- इस प्रकार, यह देखते हुए कि यह पंचाट उसके अधिकार क्षेत्र से परे है, अवैध है, और इसे रद्द किया जाता है।

एस. 30 (ए) - मध्यस्थ द्वारा कदाचार-धारणा का अर्थ: "कदाचार" में मध्यस्थ द्वारा किए गए कार्य तथा वे युक्तियुक्त सिद्धान्त शामिल हैं जिनके परिणामस्वरूप ऐसा पंचाट या अन्यायपूर्ण परिणाम निकला है।

मध्यस्थता-मध्यस्थ का अधिकार क्षेत्र: मध्यस्थ को अनुबंध की शर्तों के भीतर काम करना है-अनुबंध से जानबूझकर प्रस्थान न केवल उसके अधिकार की अवहेलना या उसकी ओर से कदाचार को दर्शाता है, बल्कि यह एक दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई के समान हो सकता है- यदि मध्यस्थ अनुबंध के निर्माण में त्रुटि करता है, तो यह उसके अधिकार

क्षेत्र के भीतर एक त्रुटि है - यदि वह अनुबंध के बाहर घूमता है और उसे आवंटित नहीं किए गए मामलों से निपटता है, तो यह एक क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि होगी।

अपीलकर्ता-ठेकेदार ने एक कंस्ट्रक्शन कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित कीं। उत्तरदाताओं की निविदा स्वीकार कर ली गई। पार्टियों ने एक अनुबंध किया जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि कार्य सी.पी.डब्ल्यू.डी. के अनुसार निष्पादित किया जाना था। विशेष विवरण- इसमें प्रावधान था कि दर में सामग्री और श्रम की लागत शामिल होगी। पक्षों के बीच विवाद हो गया। मध्यस्थता समझौता लागू किया गया था। मध्यस्थ के समक्ष, उत्तरदाताओं ने रुपये का दावा उठाया। 5487.34 घन मीटर रेत की कीमत 8,23,101/- थी, इस आधार पर कि फर्श के नीचे प्लिंथ भरने के लिए उनके द्वारा उद्धृत दर केवल श्रम के लिए थी और उक्त के लिए रेत प्रदान करना या आपूर्ति करना शामिल नहीं था।

उद्देश्य और चूंकि उन्होंने ऐसी भराई के लिए रेत की आपूर्ति की थी, वे रेत की कीमत के लिए अतिरिक्त भुगतान के हकदार थे। मध्यस्थ ने प्रतिवादी-दावेदारों के पक्ष में एक निर्णय पारित किया। उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश और खंडपीठ दोनों ने फैसले को बरकरार रखा। इसलिए वर्तमान अपील दायर की गई ।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि दावा संख्या 9 के विरुद्ध रेत की आपूर्ति का दावा स्पष्ट रूप से पार्टियों के बीच अनुबंध की शर्तों के विपरीत था; कि अनुबंध का प्रासंगिक खंड स्पष्ट, असंदिग्ध है और मध्यस्थ द्वारा दी गई ऐसी किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करता है, और यह कि मध्यस्थ ने दावेदारों के पक्ष में अतिरिक्त राशि देने में स्वयं कदाचार किया है, पंचाट का कौन सा हिस्सा रद्द किए जाने योग्य है।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए-अभिनिर्धारित:

1.1. मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 30 के तहत आपत्तियों पर विचार करते समय, न्यायालय पंचाट में हस्तक्षेप कर सकता है जब मध्यस्थ ने स्वयं या कार्यवाही में 'कदाचार' किया हो। अधिनियम की धारा 30 (ए) में "कदाचार" शब्द आवश्यक रूप से कदाचार या धोखाधड़ी या अनुचित आचरण या नैतिक चूक को नहीं मानता है या इसमें शामिल नहीं करता है, लेकिन मध्यस्थ की ओर से कार्यों को समझता है और इसमें शामिल करता है, जो निर्णय के देखने पर प्रकट होता है। जो कि सभी तर्कसंगत और उचित सिद्धांतों का विरोध करते हैं जिसके परिणामस्वरूप पारित पंचाट या अन्यायपूर्ण परिणाम प्रकट हुआ है। [पैरा 10] [1166-सी, डी]

यूनियन ऑफ इंडिया बनाम जैन एसोसिएट्स और अन्य, [1994] 4 एससीसी 665, पर विश्वास किया गया ।

2.1. मध्यस्थ पक्षों के बीच समझौते का एक प्राणी मात्र होने के नाते, उसे समझौते के चारों कोनों के भीतर काम करना होता है और यदि वह अनुबंध की विशिष्ट शर्तों की अनदेखी करता है, तो यह पंचाट में अधिकार क्षेत्र संबंधी त्रुटि का प्रश्न होगा। कानूनी कदाचार के दायरे में जिसे न्यायालय द्वारा ठीक किया जा सकता है। हालाँकि, यदि मध्यस्थ अनुबंध के शर्तों में कोई त्रुटि करता है, तो यह उसके अधिकार क्षेत्र में एक त्रुटि है। लेकिन, यदि वह अनुबंध के बाहर जाता है और उसे आवंटित नहीं किए गए मामलों से निपटता है, तो वह क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि करता है। [पैरा 11] [1166-ई, एफ)

2.2. एक मध्यस्थ अपना अधिकार अनुबंध से प्राप्त करता है और यदि वह अनुबंध की अवहेलना करता है, तो वह अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य करता है। अनुबंध से जानबूझकर हटना न केवल उसके अधिकार की अवहेलना या उसकी ओर से कदाचार

के समान है, बल्कि यह एक दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई के समान हो सकता है। [पैरा 15]
[1167-एफ,जी]

एसोसिएटेड इंजीनियरिंग कंपनी बनाम आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य, [1991] 4 एससीसी 93; राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड बनाम ईस्टर्न इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेज एंड अन्य, [1999] 9 एससीसी 283; एमएस। अलोपी प्रसाद एंड संस लिमिटेड बनाम भारत संघ, एआईआर (1960) एससी 588; नैहाटी जूट मिल्स लिमिटेड बनाम ख्यालीराम जगन्नाथ, एआईआर (1968) एससी 522; कॉन्टिनेंटल कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य, [1988] 3 एससीसी 82 और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बनाम अन्नपूर्णा कंस्ट्रक्शन, [2003] 8 एससीसी 154, पर भरोसा किया गया।

3.1. समझौते की शर्तों से यह स्पष्ट है कि अनुबंध 3 को सी.पी.डब्ल्यू.डी. के अनुसार निष्पादित किया जाना था। विशेष विवरण। उक्त विशिष्टताओं के पैरा 2.9.4 के अनुसार, बोली लगाने वाले द्वारा उद्धृत दर गोदामों के कंस्ट्रक्शन के लिए आवश्यक दोनों वस्तुओं, अर्थात् श्रम और सामग्री, के लिए होनी चाहिए, खासकर जब यह एक टर्न की परियोजना थी। परियोजना को पूरा करने के लिए फर्श के नीचे प्लिंथ को रेत से भरने पर समझौते के तहत विचार किया गया था, लेकिन श्रम और सामग्री के लिए कोटेशन को विभाजित करने के लिए निविदा दस्तावेज में न तो कोई शर्त थी और न ही दावेदारों द्वारा उनकी बोली में ऐसा किया गया था। समझौते की शर्तों को स्वीकार करने के बाद दावेदार इसकी शर्तों से बंधे थे और मध्यस्थ भी। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि मध्यस्थ द्वारा दिया गया दावा अनुबंध की स्पष्ट शर्तों के विपरीत है। मध्यस्थ द्वारा केवल इस आधार पर अनुबंध की स्पष्ट शर्तों की अनदेखी करना उचित नहीं था कि समान कार्य के लिए एक अन्य अनुबंध में सामग्री के लिए अतिरिक्त भुगतान का

प्रावधान किया गया था। मध्यस्थ के लिए अनुबंध की शर्तों से परे जाने का अधिकार नहीं था, भले ही उसे यकीन हो कि दावेदारों द्वारा उद्धृत दर कम थी और सामग्री के लिए दूसरे ठेकेदार को अलग से भुगतान किया गया था। दावेदारों के दावे का निर्णय एफसीआई के साथ उनके समझौते की विशिष्ट शर्तों के आधार पर किया जाना था, किसी अन्य के आधार पर नहीं। [पैरा 19][1168-एफ, जी; 1169-ए-बी]

3.2. रेत की आपूर्ति के लिए अतिरिक्त भुगतान देकर मध्यस्थ ने अनुबंध की सीमाओं का उल्लंघन किया है। यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी ओर से यह त्रुटि अनुबंध की शर्तों की गलत व्याख्या के कारण हुई है, बल्कि यह अनुबंध की अवहेलना थी, जो स्पष्ट रूप से अनुबंध में स्पष्ट शर्तों की अनदेखी थी। ऐसा करके, मध्यस्थ ने खुद को गलत दिशा में निर्देशित किया और कदाचार किया। इसलिए, दावा संख्या 9 के संबंध में मध्यस्थता द्वारा दिया गया निर्णय, प्रथम दृष्टया, उसके अधिकार क्षेत्र से परे है; अवैध है और अलग रखा गया है।[पैरा 20] [1169-सी, डी]

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: 2007 की सिविल अपील संख्या 1874,

बॉम्बे में न्यायिक उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 14.10.2005 से 2005 की अपील संख्या 861 और 862 में।

अपीलकर्ता की ओर से अजीत पुडुस्सेरी।

वी.एन. शर्मा, अरुण शर्मा, पी.वी. योगेश्वरन और ए.के. शर्मा उत्तरदाताओं की ओर से ।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

डी.के. जैन, जे.

1. अनुमति स्वीकृत।

2. भारतीय खाद्य निगम (संक्षेप में "एफसीआई") द्वारा इस अपील में चुनौती, बॉम्बे उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित 14 अक्टूबर, 2005 के अंतिम निर्णय और आदेश को दी गई है, जिसमें फैसले की पुष्टि की गई है। 2004 की मध्यस्थता याचिका संख्या 334 में विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के अनुसार, दावा संख्या 9 के खिलाफ एकमात्र मध्यस्थ द्वारा 8,23,101/- रुपये की राशि के फैसले को बरकरार रखा गया है।

3. अपील को जन्म देने वाली एक संक्षिप्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि इस प्रकार है:

एफसीआई ने पनवेल, जिला रायगढ़ में गोदामों का निर्माण किया और सहायक कार्य और सेवाओं के साथ 10 इकाइयों में 50000 मीट्रिक टन क्षमता के पारंपरिक गोदामों के निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित करते हुए नोटिस जारी किया। इसके अनुसरण में, उत्तरदाताओं (वाद में दावेदारों के रूप में संदर्भित) ने निविदा प्रस्तुत की, जिसे एफसीआई ने स्वीकार कर लिया। 19 सितंबर, 1984 को एफसीआई और दावेदारों के बीच एक औपचारिक अनुबंध निष्पादित किया गया था। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, काम आदेश जारी होने के 30 वें दिन से 10 महीने के भीतर पूरा किया जाना था और समय सीमा माना गया था। अनुबंध का सार।

4. चूंकि दावेदार निर्धारित समय के भीतर काम पूरा नहीं कर सके, जिसे एक बार बढ़ा दिया गया था, एफसीआई ने अनुबंध समाप्त करने की मांग करते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया। अंततः 15 नवंबर, 1987 के आदेश द्वारा अनुबंध समाप्त कर दिया गया। दावेदारों ने मध्यस्थता समझौते का आह्वान किया और एफसीआई से एक मध्यस्थ नियुक्त करने का अनुरोध किया। चूंकि एफसीआई से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, इसलिए दावेदारों ने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय

में मुकदमा दायर किया। एक मध्यस्थ नियुक्त किया गया, जिसने 27 अगस्त, 1998 को अपना फैसला सुनाया। चूंकि फैसले के संदर्भ में भुगतान नहीं किया गया था, दावेदार फिर से उच्च न्यायालय चले गए। बदले में, एफसीआई ने पंचाट को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। पक्षों की सहमति से, पंचाट को रद्द कर दिया गया और मामले को नए जी निर्णय के लिए मध्यस्थ के पास भेज दिया गया।

5. मध्यस्थ के समक्ष ताजा कार्यवाही में, दावा संख्या 9 के बारे में दावेदारों का रुख यह था कि फर्श के नीचे प्लिंथ को पानी देने, समेकन और ड्रेसिंग के संदर्भ में भरने के लिए उनके द्वारा उद्धृत दर थी। दरों की अनुसूची की मद संख्या 1.7 केवल श्रम के लिए थी और इसमें उक्त उद्देश्य के लिए रेत "प्रदान करना या आपूर्ति करना" शामिल नहीं था और फिर भी उन्हें भरने के लिए रेत की आपूर्ति करना आवश्यक था। इस प्रकार दावेदार रेत की आपूर्ति के लिए अतिरिक्त भुगतान पाने के हकदार थे। तदनुसार, उन्होंने 5487.34 घन मीटर रेत उपलब्ध कराने और आपूर्ति करने के लिए 8,23,101/- रुपये का दावा किया।

6. दावे का एफसीआई ने इस आधार पर विरोध किया था कि काम का दायरा, विनिर्देश और आइटम दरें अनुबंध की शर्तों और दिनांक 19 सितंबर, 1984 के समझौते के खंड (2) के अनुसार नियंत्रित होती थीं, दावेदार संलग्न अनुसूची में निहित 'दरों की अनुसूची' पर उसके द्वारा वास्तव में किए गए काम के लिए संबंधित राशि और इस अनुबंध के प्रावधानों के तहत ठेकेदार को देय अन्य रकम का भुगतान किया जाना था। अनुबंध में स्पष्ट रूप से बताया गया है निर्धारित किया गया था कि काम सी.पी.डब्ल्यू.डी. मैनुअल के खंड I और II, पैरा 2.9.4 में निहित विनिर्देशों के अनुसार किया जाना था, बशर्ते कि "दर" में सामग्री और श्रम की लागत शामिल हो। इसलिए,

दावेदार किसी भी हकदार नहीं थे रेत की आपूर्ति के लिए अतिरिक्त राशि। मध्यस्थ ने उक्त दावे को स्वीकार करते हुए 31 दिसंबर, 2003 को अपना फैसला सुनाया। संदर्भ के लिए, फैसले का प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया है:

"1967 सीपीडब्ल्यूडी विनिर्देश खंड I और II के प्रावधान के तहत ली गई प्रतिरक्षा के अनुसार, वस्तु की प्रकृति में रेत भी शामिल है और न केवल श्रम शुल्क, इसी तरह रेत भरने की दर समेकित मोटाई या ढीली मोटाई या किसी भी हद तक खालीपन के लिए है और इस दावे को खारिज कर दिया गया है। अब यहां दोनों पक्षों के बीच विवाद आपूर्ति और प्रदान करने वाले शब्दों को लेकर है और इस आइटम के संबंध में विशेष शब्द गायब हैं, जबकि जैसा कि पहले देखा गया था, वे कुछ अन्य वस्तुओं के संबंध में पाए जा रहे थे। दावेदारों को चूंकि काम की इस मद के संबंध में ये शब्द गायब थे, इसलिए उन्होंने मान लिया कि सामग्री यानी रेत की आपूर्ति की जाएगी और इसलिए, उन्होंने केवल श्रम दर उद्धृत की। मेसर्स गुप्ता एंड कंपनी की निविदा के रूप में मुझे बताया गया, यह दर्शाता है कि कार्य की इस वस्तु के संबंध में, प्रदान करना और आपूर्ति करना इन शब्दों का उपयोग किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि एक ही वस्तु के संबंध में दो अलग-अलग शब्दावलियां नहीं हो सकती हैं और जैसा कि पहले देखा गया है, एफसीआई को किसी भी चीज ने रोका नहीं है। उन शब्दों के प्रयोग से और किसी भी भ्रम की स्थिति पैदा न हो। पीडब्ल्यूडी बॉम्बे के साथ काम करने वाले टेंडर के आधार पर अनुसूची वस्तुओं की सामग्री और विवरण दिखाने वाला तुलनात्मक विवरण जो स्पष्ट रूप से अनुसूची वस्तुओं के लिए काम की मात्रा के लिए दरें प्रदान करता है। यहां दावेदार यह स्थापित करने की

कोशिश कर रहे हैं कि उनकी कोटेशन आपूर्ति की गई सामग्रियों की दर लागत को शामिल किए बिना थीं। यदि हम वस्तुओं के संबंध में आंकड़ों को देखें, तो दावेदारों की बात को पर्याप्त बल मिलता है कि उनके द्वारा उद्धृत दर इतनी कम है कि यह रेत की लागत सहित कीमत के संबंध में नहीं हो सकती है। यदि हम ठेकेदार के साथ विनिर्देश के शब्दों को देखते हैं। गुप्ता एंड कंपनी, हमने पाया कि अनुसूची की समान वस्तुओं के तहत अतिरिक्त शब्द आपूर्ति और प्रदान करना जोड़ा गया है। दावेदारों के मामले में ये शब्द क्यों गायब थे, इसका पालन करना मुश्किल है। उत्तरदाताओं का कहना है कि खंड 1 और 11 में 1967 सीपीडब्ल्यूडी के विनिर्देशन में न केवल श्रम शुल्क के लिए बल्कि आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने और आपूर्ति के लिए भी विनिर्देश शामिल हैं। इस बचाव को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर हम निविदाओं में उद्धृत आंकड़ों को देखें तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि रेत की लागत को शामिल करने की बात ठेकेदार के दावेदारों के दिमाग में नहीं हो सकती है। आंकड़े बहुत कम हैं और मुझे यह कहने की अनुमति दी जा सकती है कि ये आंकड़े रेत की लागत को कवर नहीं करते हैं। दावेदार की बात में दम है कि उसने इस बात की गारंटी नहीं दी कि उसे खुद ही रेत की आपूर्ति करनी थी। बेशक, मुझे कहना होगा कि इस्तेमाल की गई रेत की मात्रा, उसकी कीमत और दावेदार द्वारा अपने आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई राशि के बारे में कोई बहुत संतोषजनक सबूत नहीं है, लेकिन जब काम पूरा हो गया तो एफसीआई भुगतान करने के लिए बाध्य था। यह कुछ हद तक मनमाना प्रतीत हो सकता है। मैं 8,23,101/- (आठ

लाख तेईस हजार एक सौ एक रुपये मात्र) के इस दावे की अनुमति देता हूं।"

7. व्यथित होकर, एफसीआई ने भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 30 के तहत फैसले के खिलाफ आपत्तियां दर्ज कीं और दावा संख्या 9 पर फैसले को रद्द करने की प्रार्थना की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। विद्वान एकल न्यायाधीश ने मध्यस्थ द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की पुष्टि की कि दावेदार द्वारा उद्धृत दर में सामग्री की लागत शामिल नहीं है। एफसीआई ने मामले को डिवीजन बेंच के समक्ष अपील में उठाया। डिवीजन बेंच के समक्ष, एफसीआई ने मध्यस्थ द्वारा ब्याज देने के मुद्दे को उठाने का भी प्रयास किया, जिसे इस आधार पर अनुमति नहीं दी गई कि यह मुद्दा न तो मध्यस्थ के समक्ष उठाया गया था और न ही विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष उठाया गया था। जैसा कि ऊपर बताया गया है, डिवीजन बेंच ने अपील खारिज कर दी है। इसलिए, वर्तमान अपील।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि दावा संख्या 9 के विरुद्ध रेत की आपूर्ति का दावा स्पष्ट रूप से पार्टियों के बीच अनुबंध की शर्तों के विपरीत था। यह आग्रह किया जाता है कि अनुबंध का प्रासंगिक खंड स्पष्ट, असंदिग्ध है और इसमें ऐसी कोई व्याख्या नहीं है जो मध्यस्थ द्वारा दी गई है। इस प्रकार, दलील दी गई है कि मध्यस्थ ने दावेदारों के पक्ष में 8,23,101/- रुपये की अतिरिक्त राशि का फैसला देने में खुद से दुरु्यवहार किया है, फैसले का वह हिस्सा रद्द किए जाने लायक है।

9. दूसरी ओर, दावेदारों के विद्वान वकील ने कहा कि दावेदारों द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए साक्ष्यों के आलोक में अनुबंध की शर्तों को समझना मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र में था, विशेष रूप से एफसीआई द्वारा अन्य ठेकेदारों के साथ किए गए समान अनुबंधों

की शर्तों के आधार पर। यह दावा किया गया है कि मध्यस्थ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण उच्च न्यायालय के प्रशंसनीय होने के कारण पंचाट में हस्तक्षेप करने से इनकार करना उचित था।

10. मध्यस्थता अधिनियम, 1940 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 30 के तहत आपत्तियों पर विचार करते समय, किसी पंचाट को रद्द करने का न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सीमित है। धारा में निर्धारित आधारों में से एक, जिस पर न्यायालय पंचाट में हस्तक्षेप तब किया जा सकता है जब मध्यस्थ ने स्वयं या कार्यवाही में 'कदाचार' किया हो। "कदाचार" शब्द को न तो अधिनियम में परिभाषित किया गया है और न ही न्यायालय के लिए इसे विस्तृत रूप से परिभाषित करना या उन मामलों की श्रृंखला को सूचीबद्ध करना संभव है जिनमें अकेले हस्तक्षेप या तो किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। फिर भी, अधिनियम की धारा 30 (ए) में "कदाचार" शब्द आवश्यक रूप से कदाचार या धोखाधड़ी या अनुचित आचरण या नैतिक चूक को नहीं समझता या शामिल करता है, बल्कि इसमें कुछ कार्यों को शामिल किया गया है। मध्यस्थ के, जो प्रथम दृष्टया निर्णय देने के लिए सभी तर्कसंगत और उचित सिद्धांतों का विरोध करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक पंचाट या अन्यायपूर्ण परिणाम होता है। (भारत संघ बनाम जैन एसोसिएट्स और अन्य)

11. यह कहना उचित नहीं है कि मध्यस्थ पक्षों के बीच समझौते का प्राणी होने के कारण, उसे समझौते के चारों कोनों के भीतर काम करना होता है और यदि वह अनुबंध की विशिष्ट शर्तों की अनदेखी करता है, तो यह क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि का प्रश्न होगा पंचाट की दृष्टि से, कानूनी कदाचार के दायरे में आता है जिसे न्यायालय द्वारा ठीक किया जा सकता है। हालाँकि, हम यह जोड़ने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि यदि मध्यस्थ अनुबंध के कंस्ट्रक्शन में कोई त्रुटि करता है, तो यह उसके अधिकार क्षेत्र में

एक त्रुटि है। लेकिन, यदि वह अनुबंध से बाहर घूमता है और उसे आवंटित नहीं किए गए मामलों से निपटता है, तो वह एक न्यायिक त्रुटि करता है (देखें: एसोसिएटेड इंजीनियरिंग कंपनी बनाम आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य, और राजस्थान राज्य खान और खनिज लिमिटेड बनाम पूर्वी)। इंजीनियरिंग उद्यम और अन्य।)।

12. इस संदर्भ में, मैसर्स में इस न्यायालय की टिप्पणियों का उपयोगी संदर्भ दिया जा सकता है। अलोपी पार्षद एंड संस, लिमिटेड बनाम भारत संघ", जिसमें यह देखा गया कि भारतीय अनुबंध अधिनियम किसी अनुबंध के पक्ष को उसके स्पष्ट अनुबंधों की अनदेखी करने और दरों पर अनुबंध के प्रदर्शन के लिए प्रतिफल के भुगतान का दावा करने में सक्षम नहीं बनाता है। इक्विटी की कुछ अस्पष्ट दलीलों पर, निर्धारित दरों से भिन्न। न्यायालय ने यह कहना जारी रखा कि भारत में, अनुबंधों के संहिताबद्ध कानून में, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस दृष्टिकोण को उचित ठहराता हो कि परिस्थितियों में बदलाव, "पार्टियों के चिंतन से पूरी तरह से बाहर" उस समय जब अनुबंध में प्रवेश किया गया था, पार्टियों को बाध्य रखते हुए, एक न्यायालय को उचित ठहराएगा। अनुबंध द्वारा, उसकी स्पष्ट शर्तों से हटकर। इसी तरह, द नैहाटी जूट मिल्स लिमिटेड बनाम ख्यालीराम जगन्नाथ मामले में, इस न्यायालय ने कहा था कि जहां एक व्यक्त शब्द है, वहां न्यायालय, अनुबंध के कंस्ट्रक्शन पर, ऐसे व्यक्त शब्द के साथ असंगत एक निहित शब्द नहीं ढूंढ सकता है।

13. कॉन्टिनेंटल कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य में, इस बात पर जोर दिया गया था कि एक मध्यस्थ होने के नाते, वह कानून की अनदेखी नहीं कर सकता है या जो वह उचित और उचित समझता है उसे करने के लिए कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। वह अपने विवादों को कानून के अनुसार तय करने के लिए पार्टियों द्वारा चुना गया एक न्यायाधिकरण है और इसलिए कानून का पालन करने

और लागू करने के लिए बाध्य है, और यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो उसे अदालत द्वारा सही ठहराया जा सकता है, बशर्ते उसकी त्रुटि पंचाट के चेहरे पर दिखाई दे। .

14. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बनाम अन्नपूर्णा कंस्ट्रक्शन के मामले में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह देखते हुए कि मध्यस्थ मनमाने ढंग से, तर्कहीन, सनकी या अनुबंध से स्वतंत्र कार्य नहीं कर सकता है, यह इस प्रकार देखा गया था:

"क्षेत्राधिकार के भीतर त्रुटि और क्षेत्राधिकार से अधिक की त्रुटि के बीच स्पष्ट अंतर है। इस प्रकार, मध्यस्थ की भूमिका अनुबंध की शर्तों के भीतर मध्यस्थता करना है। पार्टियों ने उसे जो कुछ दिया है उसके अलावा उसके पास कोई शक्ति नहीं है। अनुबंध। यदि उसने अनुबंध से परे यात्रा की है, तो वह अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य कर रहा होगा, जबकि यदि वह अनुबंध के मापदंडों के भीतर रहा है, तो उसके पंचाट पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है कि इसमें रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट त्रुटि है।"

15. इसलिए, इस बात पर थोड़ा जोर देने की आवश्यकता है कि एक मध्यस्थ अपना अधिकार अनुबंध से प्राप्त करता है और यदि वह अनुबंध की अवहेलना में कार्य करता है, तो वह अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य करता है। अनुबंध से जानबूझकर विचलन न केवल उसके अधिकार की अवहेलना या उसकी ओर से कदाचार को दर्शाता है, बल्कि यह एक दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई के समान हो सकता है [यह भी देखें: एसोसिएटेड इंजीनियरिंग कंपनी बनाम आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य, (सुप्रा)].

16. इस प्रकार, निर्धारण के लिए जो मुद्दा उठता है, वह यह है कि क्या दावा संख्या 9 देने में मध्यस्थ ने पार्टियों के बीच समझौते की अवहेलना की है और इस

प्रक्रिया में अपने अधिकार क्षेत्र से आगे निकल गया है और इस प्रकार, कानूनी कदाचार का अपराध किया है ?

17. विवाद पर निर्णय लेने के लिए, अनुबंध के प्रासंगिक खंडों को संदर्भित करना आवश्यक होगा, जो इस प्रकार हैं:

"1. सामान्य विशिष्टताएँ:

1.1 सिविल सेनेटरी, जल आपूर्ति और सड़क कार्य केंद्रीय लोक कंस्ट्रक्शन विभाग के दिल्ली 1967 खंड I और II के कार्यों के विनिर्देशों के अनुसार अद्यतन परिचियों के साथ किए जाएंगे... सिविल, सेनेटरी, जल आपूर्ति के मामले में और सड़क कार्य और बिजली के कार्यों में ऊपर उल्लिखित केंद्रीय लोक कंस्ट्रक्शन विभाग के विनिर्देशों और मात्राओं की अनुसूची के विनिर्देशों के बीच कोई अंतर होना चाहिए, बाद वाला यानी मात्राओं की अनुसूची का विनिर्देश मान्य होगा। सी.पी.डब्ल्यू.डी. में शामिल न किए गए कार्यों की मदों के लिए। विनिर्देशों या जहां सी.पी.डब्ल्यू.डी. विनिर्देश किसी विशेष बिंदु पर मौन हैं, भारतीय मानक संस्थान के प्रासंगिक विनिर्देशों या अभ्यास संहिता का पालन किया जाएगा।

1.2 यदि किसी कार्य की विशिष्टताओं के संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो प्रभारी अभियंता से लिखित निर्देश प्राप्त किए जाएंगे।"

18. सी.पी.डब्ल्यू.डी. का पैराग्राफ 2.9.4. जहाँ तक यह वर्तमान अपील के लिए प्रासंगिक है, विनिर्देश इस प्रकार हैं:

"दर:- इसमें ऊपर वर्णित सभी कार्यों में शामिल सामग्री और श्रम की लागत शामिल है।"

19. एफसीआई और दावेदारों के बीच समझौते की उपरोक्त निकाली गई शर्तों से, यह स्पष्ट है कि अनुबंध को सी.पी.डब्ल्यू.डी. के अनुसार निष्पादित किया जाना था। विशेष विवरण। उक्त विशिष्टताओं के पैरा 2.9.4 के अनुसार, बोली लगाने वाले द्वारा उद्धृत दर गोदामों के कंस्ट्रक्शन के लिए आवश्यक दोनों वस्तुओं, अर्थात् श्रम और सामग्री, के लिए होनी चाहिए, खासकर जब यह एक टर्नकी परियोजना थी। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि परियोजना को पूरा करने के लिए फर्श के नीचे प्लिंथ को रेत से भरने पर समझौते के तहत विचार किया गया था, लेकिन श्रम और सामग्री के लिए कोटेशन को विभाजित करने के लिए निविदा दस्तावेज में न तो कोई शर्त थी और न ही ऐसा किया गया था। दावेदारों द्वारा अपनी बोली में किया गया। दावेदारों ने खुली आँखों से अपनी निविदा प्रस्तुत की थी और यदि उनके अनुसार रेत की कीमत उद्धृत दरों में शामिल नहीं की गई थी, तो उन्होंने अनुबंध के निष्पादन के किसी चरण में विरोध किया होगा, जो यहां मामला नहीं है। 19 सितंबर, 1989 के समझौते की शर्तों को स्वीकार करते हुए, वे अपनी शर्तों से बंधा हुआ था और मध्यस्थ भी ऐसा ही था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि मध्यस्थ द्वारा दिया गया दावा अनुबंध की स्पष्ट शर्तों के विपरीत है। हमारा विचार है कि मध्यस्थ द्वारा केवल इस आधार पर अनुबंध की स्पष्ट शर्तों की अनदेखी करना उचित नहीं था कि समान कार्य के लिए एक अन्य अनुबंध में, सामग्री के लिए अतिरिक्त भुगतान प्रदान किया गया था। मध्यस्थ के लिए अनुबंध की शर्तों से परे जाने का अधिकार नहीं था, भले ही वह आश्वस्त था कि दावेदारों द्वारा उद्धृत दर कम थी और एक अन्य ठेकेदार, अर्थात् मेसर्स गुसा एंड कंपनी को सामग्री के लिए अलग से भुगतान किया गया था। दावेदारों के दावे का निर्णय एफसीआई के साथ उनके समझौते की विशिष्ट शर्तों के आधार पर किया जाना था, किसी अन्य के आधार पर नहीं।

20. इसलिए, हमारे विचार में, रेत की आपूर्ति के लिए अतिरिक्त भुगतान देकर मध्यस्थ ने अनुबंध की सीमा को पार कर लिया है। यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी ओर से यह त्रुटि अनुबंध की शर्तों की गलत व्याख्या के कारण हुई है, बल्कि यह अनुबंध की अवहेलना थी, जो स्पष्ट रूप से अनुबंध में स्पष्ट शर्तों की अनदेखी थी। हमारी राय में, ऐसा करके मध्यस्थ ने खुद को गलत दिशा दी और कदाचार किया। इसलिए, दावा संख्या 9 के संबंध में मध्यस्थता द्वारा दिया गया निर्णय, प्रथम दृष्टया, उसके अधिकार क्षेत्र से परे है; यह अवैध है और इसे अलग रखा जाना चाहिए।

21. नतीजतन, अपील की अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले को, जिस हद तक यह दावा संख्या 9 से संबंधित है, खारिज कर दिया जाता है। हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

एन.जे.

अपील अनुमत की गई ।

1. [1994]4 एससीसी 665
2. [1991] 4 एससीसी 93
3. [1991] 9 एससीसी 283
4. एआइआर [1960] एससी 588
5. एआइआर [1968] एस सी 522
6. [1988] 3 एससीसी 82
7. [2003] 8 एससीसी 154

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी उत्तमा माथुर (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।